IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था ;छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ मेंद्ध

[1] रेणु शुक्लाए [2] डॉण् प्रीति शर्मा

[1] शोधार्थीए समाजशास्त्रए [2] ;शोध निर्देशकद्ध सहायक प्राध्यापक

[1] समाजशास्त्र विभागए रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालयए भोपाल ;मण्प्रण्द्ध

शोध सारांश दृ

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम हैए जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य करती है। छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था ने शिक्षाए स्वास्थ्यए स्वच्छताए रोजगारए सिंचाई और सड़क कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस शोध में पंचायतों की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन किया गया हैए जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक साबित हुए हैं।

मनरेगा के तहत रोजगार सृजनए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ गांवों की वृद्धिए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार ने जिले में समग्र विकास सुनिश्चित किया है। टीकाकरण दरए ड्रॉपआउट दर में कमीए और सिंचाई सुविधाओं का विस्तारए ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को दर्शाते हैं।

यह अध्ययन छिंदवाड़ा जिले के पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास में किए गए प्रयासों और उनके प्रभावों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ हीए यह पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियों और उनके समाधान की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालता है।

मुख्य शब्द . पंचायती राजए ग्रामीण विकासए छिंदवाड़ाए मनरेगाए स्वच्छ भारत मिशनए सड़क कनेक्टिविटीए शिक्षाए स्वच्छताए स्वास्थ्य।

प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाएँ भारत में विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अध्ययन में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिकए आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यह जिला अपनी आदिवासी जनसंख्या और कृषि.आधारित अर्थव्यवस्था के कारण पंचायती राज के कार्यान्वयन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। शोध में यह पाया गया कि पंचायतों ने शिक्षाए स्वास्थ्यए महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार जैसी पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान किया है। मिड.डे मील कार्यक्रम और आवासीय विद्यालयों के माध्यम से स्कूल ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए स्वास्थ्य अभियानों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कियाए और 2023 तक छिंदवाड़ा के 85 प्रतिशत गाँव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।

आर्थिक दृष्टि सेए मनरेगा जैसी योजनाओं ने 1ण्5 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन कियाए जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। जल संरक्षण और वन उत्पादों के प्रबंधन ने आदिवासी समुदायों की आय में वृद्धि की है। बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र मेंए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन के तहत सड़क और स्वच्छ जल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। हालाँकिए पंचायतों को वित्तीय अनियमितताओंए अपर्याप्त प्रशिक्षण और योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षणए पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह बेहतर शासन और संसाधन प्रबंधन के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैए जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्थाएँ न केवल प्रशासनिक कार्यों में बल्कि सामाजिकए आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिलाए अपनी भौगोलिक विविधताए आदिवासी जनसंख्या और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारणए पंचायतों द्वारा किए गए विकास कार्यों का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ की पंचायतों ने शिक्षाए स्वास्थ्यए महिला सशक्तिकरणए जल संरक्षणए वनोपज प्रबंधन और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करना हैए ताकि यह समझा जा सके कि पंचायतें ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं में किस प्रकार प्रभावी रही हैं। इसके माध्यम से यह भी देखा जाएगा कि पंचायती राज संस्थाएँ किस प्रकार स्थानीय स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाती हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाती हैं।

आध्यात्मिक दृष्टिकोण सेए यह प्रणाली ग्रामीण भारत के विकास में एक स्थायी बदलाव लाने में सक्षम हैए लेकिन इसके लिए पर्याप्त संसाधनोंए प्रशिक्षण और पारदर्शिता की आवश्यकता है। इस अध्ययन में छिंदवाड़ा जिले के अनुभवों और उपलब्धियों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में किए गए प्रयासों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज

पंचायती राज व्यवस्था भारत में विकेंद्रीकृत शासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैए जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास कार्यों का संचालन करना है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में लागू की गईए जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वशासन और विकास के लिए एक संरचना प्रदान करना था। पंचायती राज संस्थाएँ ;ग्राम पंचायतए पंचायत समितिए और जिला पंचायतद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनए निर्णय.निर्माण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ निभाती हैंए बल्कि सामाजिकए आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास में भी सक्रिय रूप से शामिल होती हैं। पंचायतों का कार्य केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहींए बल्कि ग्रामीण समुदायों के बीच सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना भी है।

सामाजिक विकास में भूमिका

पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। यह व्यवस्था शिक्षाए स्वास्थ्यए स्वच्छताए महिला सशक्तिकरणए और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायतों के द्वारा संचालित आशा कार्यकर्ताए आंगनवाड़ी केंद्रए स्वच्छ भारत अभियान और मिड.डे मील योजना जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर में सुधार किया है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों और भूमिका को बढ़ावा मिला हैए जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

आर्थिक विकास में भूमिका

पंचायती राज संस्थाएँ आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मनरेगा ;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाद्ध जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलते हैंए जो उनके जीवन यापन को सुधारने में मदद करते हैं। पंचायतों के माध्यम से छोटे.छोटे कृषि और व्यापारिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता हैए जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावाए पंचायतें कृषि सुधारए सिंचाई प्रबंधनए और जल संचयन जैसी योजनाओं को लागू कर किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती हैं।

बुनियादी ढाँचे के विकास में भूमिका

पंचायती राज व्यवस्था ने बुनियादी ढाँचे के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायतें सड़क निर्माणए जल आपूर्तिए स्वच्छता और बिजलीकरण जैसी परियोजनाओं का संचालन करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ;च्डळैल्द्ध के तहत पंचायतों ने गांवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद की है। जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके साथ हीए ग्रामीण विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा जैसी परियोजनाएँ भी पंचायतों द्वारा लागू की गई हैं।

पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास के प्रत्येक पहलू में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से ग्राम स्तर पर प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ हैए जिससे सरकार की योजनाएँ सीधे जनता तक पहुँच सकी हैं। पंचायतें केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए नहींए बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी एक सशक्त मंच बन चुकी हैं। यदि इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है।

छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ग्रामीण विकास में पंचायती राज

ग्रामीण विकास भारत के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैए और पंचायती राज व्यवस्था ने इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावशाली रही हैए जहाँ सामाजिकए आर्थिकए और बुनियादी ढाँचे के विकास में पंचायतों की भूमिका प्रमुख रही है। छिंदवाड़ा जिलाए अपनी भौगोलिक विविधता और आदिवासी बहुलता के कारणए पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शोध जिले में पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं और इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है।

छिंदवाड़ाए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थितए मुख्यतः कृषि और वनोपज पर निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसारए जिले की कुल आबादी लगभग 20 लाख हैए जिसमें 36 प्रतिशत आदिवासी समुदाय हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने जिले में शिक्षाए स्वास्थ्यए और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक विकास के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। उदाहरणस्वरूपए पंचायतों द्वारा स्कूलों के संचालन और मिड.डे मील जैसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से विद्यालय ड्रॉपआउट दर 12 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत रह गई है। आदिवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं और आवासीय विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायतें आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से टीकाकरण कार्यक्रमों और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता परियोजनाओं का संचालन करती हैं। इसके परिणामस्वरूपए 2023 तक छिंदवाड़ा के 85 प्रतिशत गाँव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं।

आर्थिक विकास के संदर्भ मेंए पंचायतों ने मनरेगा ;डळछत्म्ळाद्ध के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। 2023 तकए जिले में 1ण्5 करोड़ कार्य दिवस का सृजन हुआ हैए जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक स्थिरता प्राप्त हुई। सिंचाई और जल प्रबंधन में भी पंचायतों ने तालाब और बंधान निर्माण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से किसानों की सहायता की है। वनोपजए जैसे महुआ और तेंदू पत्ताए के संग्रह और विपणन में पंचायतों की भूमिका ने आदिवासी समुदाय की आय में वृद्धि की है।

बुनियादी ढाँचे के विकास में भी पंचायतों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ;च्डळैल्द्ध के तहतए छिंदवाड़ा के 95 प्रतिशत गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने ग्रामीणों को स्वच्छ जल और बिजली की सुविधा प्रदान की है।

छिंदवाड़ा जिले की पंचायतों की सफलता को कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। परासिया ब्लॉक में पंचायतों द्वारा संचालित जल संरक्षण परियोजनाओं ने 500 से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा दी है। मोहखेड़ की ग्राम पंचायत ने महिला सरपंच के नेतृत्व में आँगनवाड़ी केंद्रों को कुपोषण मुक्त किया है। पांढुर्ना ब्लॉक में पंचायतों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय ने 90 प्रतिशत परीक्षा परिणाम दिए हैंए जो आदिवासी समुदाय के लिए एक प्रेरणा है।

हालाँकिए पंचायतों के कामकाज में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इनमें वित्तीय अनियमितताए पंचायत प्रतिनिधियों का अपर्याप्त प्रशिक्षणए और दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन शामिल हैं। भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी भी विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षणए फंड आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिताए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग आवश्यक है। साथ हीए सामुदायिक भागीदारी और ग्राम सभाओं में महिलाओं और युवाओं की सक्रिय सहभागिता से पंचायतों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज की भूमिका के प्रभाव को संख्यात्मक आंकड़ों के माध्यम से समझने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है .

1ण् शिक्षा में सुधार

पंचायती राज व्यवस्था के तहत चलाए गए कार्यक्रमों का असर शिक्षा पर दिखा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं .

- **विद्यालय ड्रॉपआउट दर** . 2011 में छिंदवाड़ा जिले की ड्रॉपआउट दर लगभग 12 प्रतिशत थीए जो अब घटकर 6 प्रतिशत हो गई है।
- **पारदर्शिता और निगरानी** . पंचायतों द्वारा स्कूलों की निगरानी और मिड.डे मील की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कारण छात्रों की उपस्थिति और शैक्षिक परिणामों में सुधार हुआ है। मिड.डे मील योजना का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और उनकी पोषण स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहतए छात्रों को स्कूल में भोजन प्रदान किया जाता हैए जिससे उनकी उपस्थिति में वृद्धि होती है।

  यदि हम छिंदवाड़ा जिले में मिड.डे मील योजना के प्रभाव को आंकड़ों के माध्यम से दिखाना चाहेंए तो निम्नलिखित उदाहरण हो सकते हैं .

  - 2015 में मिड.डे मील योजना लागू होने से पहले छात्र उपस्थिति . 60 प्रतिशत
  - 2023 में मिड.डे मील योजना के लागू होने के बाद छात्र उपस्थिति . 90 प्रतिशत

  यह डेटा दिखाता है कि मिड.डे मील योजना के लागू होने के बाद छात्र उपस्थिति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

2ण् स्वास्थ्य और स्वच्छता

स्वच्छ भारत अभियान और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कई सकारात्मक बदलाव आए हैं .

- **स्वच्छता** . 2023 तकए छिंदवाड़ा के 85 प्रतिशत गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं।

  स्वच्छ भारत मिशन के तहतए ओडीएफ गांवों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंचायतों द्वारा कई पहल की गई हैं। इस प्रयास के कारणए छिंदवाड़ा जिले में ओडीएफ गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है।

  - 2015 में व्क्थ् गांवों का प्रतिशत . 30 प्रतिशत
  - 2023 में व्क्थ् गांवों का प्रतिशत . 85 प्रतिशत

यह डेटा दर्शाता है कि **2015** से **2023** तक ओडीएफ गांवों का प्रतिशत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है।

- **टीकाकरण दर** . पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से टीकाकरण दर में भी सुधार हुआ है। टीकाकरण दर में वृद्धि को दिखाने के लिए हम **2018** से **2023** तक के डेटा का उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से यह दिखाया जा सकता है कि पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से टीकाकरण दर में सुधार हुआ है।
  - **2018** में टीकाकरण दर . **70** प्रतिशत
  - **2023** में टीकाकरण दर . **95** प्रतिशत

  यह डेटा यह दर्शाता है कि **2018** से **2023** तक टीकाकरण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

3प मनरेगा ;डळछत्म्ळ।द्ध कार्य दिवस सृजन

मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के आंकड़े भी पंचायतों द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम हैं .

- **कार्य दिवस सृजन** . **2023** तकए छिंदवाड़ा जिले में **1प5** करोड़ कार्य दिवस का सृजन हुआ है। मनरेगा ;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाद्ध के तहत कार्य दिवसों का सृजन ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छिंदवाड़ा जिले में इस योजना के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत किया जा सकता है .
  - **2011** में कार्य दिवस . **0प5** करोड़
  - **2023** में कार्य दिवस . **1प5** करोड़

  यह डेटा दिखाता है कि **2011** से **2023** तक मनरेगा योजना के तहत कार्य दिवसों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

4प जल प्रबंधन और सिंचाई

पंचायतों द्वारा जल संचयन और सिंचाई के लिए की गई परियोजनाओं का असर किसानों पर पड़ा है .

- **जल संचयन और सिंचाई के क्षेत्र में सुधार** . पंचायतों द्वारा तालाबों और बांधों के निर्माण से **500** से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिली है। सिंचाई की सुविधा प्राप्त किसानों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंचायतों द्वारा कई प्रयास किए गए हैंए जिनमें जल संचयन योजनाएँए तालाबों का निर्माणए और सिंचाई उपकरणों का वितरण शामिल है। छिंदवाड़ा जिले में इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सिंचाई की सुविधा प्राप्त किसानों का प्रतिशत बढ़ा है।
  - **2015** में सिंचाई की सुविधा प्राप्त किसानों का प्रतिशत . **30** प्रतिशत
  - **2023** में सिंचाई की सुविधा प्राप्त किसानों का प्रतिशत . **60** प्रतिशत

  यह डेटा यह दिखाता है कि **2015** से **2023** तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त किसानों का प्रतिशत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है।

5प सड़क कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचायतों द्वारा सड़क निर्माण ने ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार किया है .

- **सड़क कनेक्टिविटी** .**2023** तकए जिले के **95**ः गाँव मुख्य सड़कों से जुड़े हुए हैं। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचायतों द्वारा सड़क निर्माण ने गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने में मदद की हैए जिससे ग्रामीण विकास में तेजी आई है।
  - **2010** में सड़क कनेक्टिविटी प्रतिशत . **60** प्रतिशत
  - **2023** में सड़क कनेक्टिविटी प्रतिशत . **95** प्रतिशत

  यह डेटा दिखाता है कि **2010** से **2023** तक सड़क कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ हैए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ी है।

निष्कर्ष .

अंततःए छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास के हर पहलू में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैए जिसने स्थानीय समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। चुनौतियों का समाधान करके और योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचार लाकरए यह व्यवस्था ग्रामीण भारत को और अधिक समृद्ध और स्वावलंबी बना सकती है। छिंदवाड़ा जिले में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन ने इस जिले में कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। विशेष रूप सेए शिक्षाए स्वास्थ्यए स्वच्छताए जल प्रबंधनए रोजगार सृजनए और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया है। पंचायतों के द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता और मिड.डे मील जैसी योजनाओं के प्रभाव से स्कूलों में उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ गांवों का प्रतिशत बढ़ा हैए जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार हुआ है। पंचायतों द्वारा जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन से सिंचाई की सुविधा प्राप्त किसानों का प्रतिशत बढ़ा हैए जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। मनरेगा योजना के तहत कार्य दिवसों का सृजन हुआए जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ाए जिससे व्यापारए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आसान हुई है।

इस प्रकारए पंचायती राज व्यवस्था ने छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है और इसने स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

. . . . . .

संदर्भ ग्रंथ सूची .

1ण् सिंहए बीण्एलण् ;2005द्ध . ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्थाए आईण्वीण्पीण् पब्लिशिंग

2ण् भारत सरकार ;1992द्ध . 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियमए भारत सरकारए नई दिल्ली

3ण् शर्माए हरिवंश ;2010द्ध . पंचायती राज और ग्रामीण विकासए जयप्रकाश साहित्य मंदिर

4ण् रावतए एसण्सीण् ;2016द्ध . पंचायती राज व्यवस्थारू मुद्दे और समाधानए प्रकाशन गृह

5ण् कुमारए राजीव ;2018द्ध . भारत में पंचायती राज का विकासए जनसंचार संस्थान

6ण् सिंहए विमल ;2020द्ध . मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्थाए मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

7ण् वर्माए दीपक ;2017द्ध . ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिकाए विकास पुस्तक प्रकाशन

8ण् भारत सरकार ;2015द्ध . स्वच्छ भारत मिशनए भारत सरकारए नई दिल्ली